

स्वच्छ भारत की अपशष्टि प्रबंधन समस्या

संदर्भ

- पछिले महीने संपन्न दावोस बैठक में भारतीय नेताओं ने व्यापार के लिये खुले देश के रूप में भारत की एक प्रभावशाली तस्वीर पेश की थी। लेकिन वास्तविक रूप में भारत के कस्बों और शहरों में जीवन की गुणवत्ता उत्साहवर्द्धक नहीं है।
- ठोस अपशष्टि प्रबंधन शहरी केंद्रों को साफ रखने के लिये नगपालिकाओं द्वारा प्रदान कराई जाने वाली मूलभूत सेवाओं में से एक है। लेकिन अधिकांश नगरपालिकाओं द्वारा शहर के भीतर या बाहर एक डंपयार्ड पर ठोस अपशष्टि को बेतरतीब ढंग से जमा किया जा रहा है।
- वशिष्टज्वाओं का मानना है कि भारत अपशष्टि नपिटान और प्रबंधन की एक दोषपूर्ण प्रणाली का अनुसरण कर रहा है।

भारत में ठोस अपशष्टि प्रबंधन की स्थिति

- भारत में प्रतिदिन 150,000 टन से अधिक नगरपालिका ठोस अपशष्टि (Municipal Solid Waste-MSW) पैदा होता है। मुंबई सर्वाधिक कचरा पैदा करने वाला दुनिया का पाँचवां सबसे बड़ा शहर है।
- फरि भी केवल 83% कचरा ही इकट्ठा किया जाता है और 30% से कम कचरा उपचारित किया जाता है।
- वशिव बैंक के मुताबिक 2025 तक भारत का दैनिक अपशष्टि उत्पादन 377,000 टन तक पहुँच जाएगा।
- इसके लिये भले ही शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को दोषी ठहराया जाए, लेकिन भारत के बड़े शहरों द्वारा पैदा किया जाने वाला कचरा एक वास्तविक और मूर्त संकट है।

क्यों आवश्यक है MSW प्रबंधन?

- अपशष्टि समस्या शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिये कई सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रस्तुत करती है, जिनमें MSW प्रबंधन प्रमुख समस्या है। यह तो सर्ववदिति है ही कि शहरी अपशष्टि हमारे स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है।
- इसके अतिरिक्त आजीविका के लिये कचरे के संग्रहण, छंटनी और व्यापार में अनौपचारिक रूप से कार्यरत कूड़ा-कचरा बीनने वाले हज़ारों लोगों की दुरदशा भी एक समस्या है।
- एक अनुमान के अनुसार, कूड़ा-कचरा बीनने वाले प्रतिविरष नगरपालिका के बजट के लगभग 14% हिससे की बचत कराते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों के न्यासी के रूप में हम भी अपने कर्तव्यों का नरिवाह करने में वफिल रहे हैं।
- इसे दलिली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर किये जाने वाले अपशष्टि दहन की समस्या से समझा जा सकता है। यह अपशष्टि दहन वायु प्रदूषण की समस्या का मुख्य अवयव है।

MSW प्रबंधन की उपेक्षा क्यों?

- व्यवहारात्मक परिवर्तन द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देना भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम की प्रमुख प्राथमिकता रही है। क्लीन इंडिया डैशबोर्ड नरितर इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को ट्रैक करता है।
- इसके अनुसार, 82,607 वार्डों में से लगभग 51,734 में अब 100% डोर-टू-डोर अपशष्टि संग्रहण की सुविधा है, जो कनिवंबर 2015 में केवल 33,278 वार्डों में उपलब्ध थी।
- लगभग 88.4 मेगावाट ऊर्जा कचरा-से-ऊर्जा (waste-to-energy-WTE) परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न की जा रही है।
- लेकिन शौचालय नरिमाण और खुले में शौच की प्रथा के उन्मूलन पर असंतुलति जोर देने से ठोस अपशष्टि प्रबंधन प्रणालियों की भारी उपेक्षा हुई है।
- भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को अपशष्टि प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये अन्यथा भारत को भी आने वाले समय में भयंकर अपशष्टि संकट का सामना करना पड़ सकता है।

दक्षिण कोरिया का MSW प्रबंधन मॉडल : केस स्टडी

- दक्षिण कोरिया की अपशष्टि प्रबंधन व्यवस्था दुनिया की सबसे परिष्कृत अपशष्टि प्रबंधन प्रणालियों में से एक है। यह जानना रुचिकर हो सकता है कि किस प्रकार दक्षिण कोरिया आर्थिक विकास और अपशष्टि उत्पादन के संबंध को अलग-अलग करने में सफल रहा है।
- पछिली आधी शताब्दी में तेजी से औद्योगिकीकरण के बावजूद दक्षिण कोरिया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का ऐसा एकमात्र देश है जिसने सकल घरेलू उत्पाद में पाँच गुना वृद्धि के बाद भी MSW को 40% तक कम करने में सफलता पाई है।

पृष्ठभूमि

- 1980 के दशक तक दक्षिण कोरिया ने भी अधिकांश अन्य वकिसशील देशों की तरह अपशषिट दहन और लैंडफलि के माध्यम से अपशषिट प्रबंधन की दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया ।
- क्योंकि यह रीयूज़ और रसिाइकल जैसे जनकेंद्रति अभियानों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान माना जाता है ।
- कति 1980 के दशक के अंत में तेज़ी से बढ़ती कचरे की समस्या के मद्देनज़र दक्षिण कोरिया ने एक मात्रा आधारति कचरा शुल्क प्रणाली (Volume-based Waste Fee System) को लागू किया ।
- इसका उद्देश्य अपशषिट उत्पादन को नयित्प्रति करना, अपशषिट प्रबंधन के वत्तिपोषण के लयि अतरिकित संसाधनों को जुटाना और अधिकितम रसिाइकलिंग प्राप्त करना था ।
- इसके बाद से MSW उत्पादन में भारी कमी देखी गई है । 1990 में 30.6 मिलियन मीटरकि टन से कम होकर यह 2016 में 19.3 मिलियन मीटरकि टन हो गया है ।
- दक्षिण कोरिया अब जर्मनी के बाद दुनिया में दूसरा सर्वाधिक रसिाइकलिंग दर (60%) वाला देश है ।
- इसके अतरिकित कचरे के लैंडफलि और दहन की दर 1990 के 94% से घटकर 2016 में 38% हो गई है ।
- WTE संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादति करने के लयि इस समग्र कार्ययोजना को नीतगित प्रयासों से पूरति किया गया ।
- दक्षिण कोरिया ने 2008 में "अपशषिट संसाधन और बायोमास ऊर्जा के लयि उपाय" जारी कयि ।
- इसके तहत WTE सुवधियाँ का वसितार करने के लयि स्थानीय सरकारों को बजटीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई ।
- दुनिया का पहला लैंडफलि-आधारति हाइड्रोजन संयंत्र 2011 में दक्षिण कोरिया में बनाया गया था ।
- साथ ही 60% से अधिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कचरे से पैदा की जाती है । इसके वपिरीत भारत में पवन और सौर ऊर्जा प्रमुख अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/swachh-bharat-waste-management-problem>

